वार्षिक लक्ष्य एक सौ पाँच करोड़ रुपये आता है, जबकि इसके विपरीत राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा आबंटित धनराशि मात्र पचास करोड़ रुपये है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया जाये, तथा प्रदेश सरकार की संस्तुति के अनुसार प्रदेश में कार्यरत हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, बनारस स्टेट बैंक, नैनीताल बैंक, बरेली कारपोरेशन बैंक तथा काशीनाथ सेठ बैंक को मिलाकर एक नये उत्तरप्रदेश बैंक की स्थापना की जाये।

(v) Need to bear the entire cost of development of roads in Dhanbad by the Central Government.

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के धनबाद एवं झरिया के कोयला क्षेत्र में कोयले की ढुलाई में सुविधा एवं विधि व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण के लिए बी सी सी एल एवं राज्य लोक निर्माण विभाग के सहयोग से सर्वेक्षण के आधार पर 1983 में 220 किलोमीटर सड़कें निर्माण के लिए 67.93 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार हुआ। यह धन उपलब्ध कराने के लिए कोयले पर 9-2-83 से प्रति मीट्रिक टन 1 85 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिससे 1 जिससे 1983-85 वर्ष में 56.6 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। पहले केन्द्रीय सरकार ने इस काम को बार्डर रोड आर्गनाइजेशन एवं राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरा कराने का सोचा। बिहार सरकार ने बोर्डर रोड आर्गनाइजेशन को लेटर आफ इन्ट्रमेंट निर्गत कर दिया एवं केन्द्रीय सरकार ने उनको 98 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपया आबंटित कर दिया। ऊर्जा मंत्रालय से सचना मिलने पर राज्य लोक निर्माण विभाग ने 25.61 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 115.51 किलोमीटर सड़क के निर्माण की तैयारी पूरी कर ली। किन्तु अचानक मई, 1984 को ऊर्जा मंत्रालय के सचिव न राज्य सरकार द्वारा खर्च में 50 प्रतिशत वहन करने की शर्त लगा कर सारा काम रोक दिया। पड़ोसी राज्यों की अरबों रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का सारा खर्च वहन करने वाली केन्द्रीय सरकार का बिहार के प्रति यह व्यवहार समझ के परे हैं। गंगा पुल निर्माण में भी केन्द्र का कोई सहयोग नहीं है। जब बिहार का कोयला सारे देश के काम आता है, तो इस क्षेत्र की सड़कों के विकास का सम्पूर्ण भार बिहार पर ही क्यों ?

अत: केन्द्रीय सरकार से मै मांग करता हूं कि धनबाद क्षेत्र की सड़कों के विकास का सारा व्यय केन्द्र वहन करने का निर्णय लेकर लोक निर्माण विभाग को कार्यारम्भ करने का संकेत दें।

(vi) Need to introduce an Express Train between Calcutta and Barbil.

SHRI HARIHAR SOREN (Keonjhar)**: Barbil-Banspani sector is famous for mines not only in Orissa but all over India. Thousands of peop'e from Bihar, West Bengal, UP, Delhi and Punjab earn their livelihood in various mines or business organisations of this mineral belt Therefore, a large number of people go to Calcutta, Delhi and other cities from this place But it is regrettable that the communication facilities available between Barbil and other cities in general and Calcutta in particular are very inadequate. Therefore, the people going from or coming to these cities face a number of difficulties

Besides, the regional offices of many organisations and mines under operation in this mineral belt are situated at Calcutta

**The Original speech was delivered in Oriya.

and, therefore, these people have to go to Calcutta every day in connection with their official work or business purpose. If a direct train is introduced between Calcutta and Barbil, thousands of people working in this area will be benefited to a large extent. In view of this, I request the hon. Minister of Railways to take immediate steps for the introduction of an Express train between Calcutta and Barbil. I also demand that the Amritsar-Tatanagar Express train be extended upto Barbil.

(vii) Need to hand over the Dhandi-Khera Samadhi in Haryana to Archaeological Department for its proper maintenance.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा जिला जींद, तहसील व गांव नरवाणा में एक पुरानी समाधि है, जिसको ढांढी खेड़ा कहते हैं। उस जगह को लोग धार्मिक जगह मान कर पूजा करते हैं और आये साल वहां मेला लगता है। यह सदियों साल पुरानी है। वहां पर हजारों यात्री आते हैं और अपनी धार्मिक आस्था से शान्ति प्राप्त करते हैं। अभी इसी महीने की 18 तारीख को पुलिस और म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने जबरन डेरा उजाड़ना चाहा और बाबा की दाढ़ी उखाड़ ली। कई हजार किसान नर-नारी इकट्ठे हुए और प्रदर्शन हुआ। मैं मोके पर पहुंच गया, जिससे कि साम्प्रदायिकता भड़कने से रुक गई और इलाके की पंचायत ने बीच-बचाव किया। केन्द्र सरकार को चाहिए कि इस वक्त जबकि देश में पृथकतावाद और साम्प्रदायिकता बढ़ गई हो, वह ऐसे मामलों को न छेड़े। यह जमीन समाज को और समाज के पास रहे। बाबा और मंदिर की जिन पुलिस अफसरों ने बेइज्जती की है, उनके खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा जांच कराई जाए, ताकि साम्प्रदायिकता घट सके। मेरा यह भी अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस स्थान के महत्व को देखते हुए इसे पुरातत्व विभाग के संरक्षण में दे, ताकि इसका रख-रखाव ठीक प्रकार से हो सके।

(vii) Need for comprehensive scheme for crop insurance.

SHRI M. RAMANNA RAI (Kasaragod): Even after 37 years since achieving independence, sufficient protection is not provided to the farmers. To a large extent, the success or failure of crops is dependent on the vagaries of monsoon. Cyclones and floods occasionally cause havoc. Years of hard work and huge investment is lost within a couple of hours Adequate insecticides are not available in time. As a result, the farmers generally feel insecure and not bolb enough to invest adequately, because of the incidence of heavy risk.

Many kisan organisations throughout India, particularly the India All Kisan Sabha have been pressing for introducing a crop insurance scheme since last many years. But till now, neither the State Governments nor the Central Government came forward with any scheme of crop insurance.

In a welfare State, the Government is not justeified in ignoring the largest section of the people, the farmers to their fate, as it is duty-bound and obliged to redress the genuine grievances of all the classes of the people, including the agriculturists.

Hence I earnestly request the Government of India to come forward with a comprehensive scheme to introduce and implement a Crop Insurance Scheme immediately throughout the country.

———